(b) No. Sir.

(c) No specific instance has been reported.

(d) No, Sir.

Supply of HR sheets by SAIL to North Bihar Development Authorities

1510. SHRI RAM AWADHESH SINGH: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 10 thousand tonnes of HR Sheets or coils were allotted to North Bihar Development Authorities in April, 1991 and the same were concealed;

(b) the number of false manufacturing companies situated in the North Bihar and South Bihar with their manufacturing capacity; and the quantity that is supplied to them annually by SAIL;

(c) The details of the orders placed by Government with these companies in terms of quantum and price; and

(d) whether Government propose to institute an enquiry in the affairs?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL (SHRI SONTOSH MOHAN DEV): (a) There was no supply of 10,000 tonnes of HR sheets or coils to North Bihar Development Authorities by Steel Authority of India Limited, in April, 1991.

(b) No such information is available.

(c) No such information is available.

(d) No, Sir.

Production of Steel

1511. SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) what is the total production of steel at present;

(b) the name of the State where maximum steel is produced; and

(c) what was the total export of steel during 1989 and whether the export increased in subsequent years?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL (SHRI SONTOSH MOHAN DEV): (a) The total production of finished steel during the year 1991-92 is estimated to be about 14-5 million tonnes.

(b) Production figures of steel are not compiled on State-wise basis.

(c) The total export of steel during the year 1989 was 299,000 tonnes. It is a fact that in subsequent years, exports have increased.

विभिन्न क्षेत्रों का निजीकरण

1512. **मौलाना अबैदुल्ला खान आज़मी:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में विभिन्न क्षेत्रों में निजीकरण शुरू किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव): (क) और (ख) इस्पात मंत्रालय के सरकारी क्षेत्र के किसी उपक्रम के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है । हालांकि सरकार ने अप-नियोजन किया है और स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के साम्य शेयरों के एक भाग को वित्तीय संस्थाओं/म्यूचुवल फण्डों को बेचा है । मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन के लिए भी इसी प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं। वित्तीय कठि-नाइयों को ध्यान में रखते हुए एस बी आई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड को इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड की आधुनिकीकरण योजनाओं को हाथ में लेने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी की सम्भावनाओं का पता लगाने का कार्य सौंपा गया है । चयनात्मक आधार पर खनन क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी की भी गुंजाइश है ।

Export targets of SAIL

1513. SHRI P. UPENDRA: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) whether Steel Authority of India Limited is unlikely to fulfil the export targets in the current year;

(b) What are the targets for export fixed this year and what percentage of it is likely to be fulfilled;

(c) the reasons for decline in exports; an

(d) what are the steps Government have taken to push up Steel exports?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL (SHRI SON-TOSH MOHAN DEV): (a) Yes, Sir.

(b) A target of 3 lakh tonnes of export of mild steel items by SAIL was fixed for this year. The likely percentage fulfilment of this target will be about 65 %.

(c) Export of specific products depends upon demand in the international market. Exports have declined due to recessionary trend in the international steel trade and reduction in foreign demand.

(d) The broad strategy recommended by the Working Group on Iron & Steel for the Eighth Plan includes renovation and technological upgradation of existing integrated steel plants, creation of additional capacities and increasing production in the secondary sector, emphasis on export of value added products, etc. De-licensing of steel sector has been allowed so as to ensure establishment of new plants in the private sector.

इस्पात का निर्यात

1541. **श्री महेन्द्र सिंह लाठर:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड तथा इस्पात का निर्माण करने वाली अन्य इकाइयां इस्पात का निर्यात कर रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत द्वारा निर्यातित इस्पात का वर्षवार ब्यौरा क्या है और उनसे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है ;

(ग) क्या सरकार हरियाणा, दिल्ली और बिहार में स्थित इस्पात संयंत्रों में निर्मित इस्पात तथा इस्पात उत्पादों का निर्यात करने का विचार रखती है और यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(घ) 1992-93 में सरकार द्वारा निर्यात किये जाने के लिए प्रस्तावित इस्पात की कुल मात्रा कितनी है तथा उसमें स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड और बोकारो इस्पात संयंत्र का संभावित हिस्सा कितना है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, हां

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान मुख्य उत्पादकों द्वारा निर्यात किए गए मृदु इस्पात की मात्रा तथा उसका मूल्य निम्नानसार है :--

मात्रा : हजार टन, मूल्य : करोड़ रुपये

1989-90		1990-91		1991-92*	
मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
298	142	311	181	277	205

*(केवल अप्रैल, 1991 से दिसम्बर, 1991 तक)